an>

Title: Need to extend financial assistance to the ESIC hospitals run by State Governments on the lines of ESIC hospitals run by Central Government.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल **(मेरठ):** मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

हमारे देश में ईएसआईसी के अस्पतालों का स्तर बहुत ही दयनीय होने के कारण करोड़ों मजदूर और उनके परिजन शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत कष्ट पा रहे हैं। अधिकांश राज्यों में ईएसआईसी अस्पतालों का संचालन प्रदेश सरकारों के द्वारा किया जाता है। इन अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का स्तर केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे मॉडल ईएसआईसी अस्पतालों से बहुत ही नीचा और घटिया है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के लिए मजदूर और नियोक्ता प्रतिमाह अपना अंशदान सीधे केन्द्र सरकार को देते हैं। मजदूर/कामगार से प्रतिमाह उसके वेतन का 1.75 प्रतिशत अंशदान काटकर नियोक्ता अपने हिस्से का 4.75 प्रतिशत अंश उसमें मिलाकर यह धनराशि सीधे केन्द्र सरकार को भेजता है और केन्द्र इस मद में प्राप्त कुल धन का 1/8 भाग राज्य सरकारों को इस योजना के अस्पतालों/औषधालयों के संचालन के लिए दे देता है। ईएसआईसी योजना में श्रमिक से किए गए वादों के विरूद्ध प्रदेश सरकारों द्वारा चलाए जा रहे ईएसआईसी अस्पतालों की हालत इस कदर खराब है कि अस्पतालों में कोई श्रमिक जाना ही नहीं चाहता तथा कर्ज लेकर प्राइवेट व महंगे अस्पतालों में अपने परिजनों का इलाज कराने को मजबूर हो जाता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश सरकारों द्वारा चलाए जा रहे ईएसआईसी चिकित्सालयों/औषधालयों (Hospitals/Dispensaries) का स्तर केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों के समकक्ष बनाना सुनिश्चित कराया जाए तथा इन चिकित्सालयों/औषधालयों के संचालन की केन्द्र सरकार द्वारा नियमित निगरानी का तंत्र विकसित किया जाए ताकि 1.5 करोड़ मजदूरों सहित लगभग 6.5 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक सीधे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकें।